



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229745
CG-DL-E-17092021-229745

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943

No. 273]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/BHADRA 26, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

(मामला सं. एडी-ओआई-12/2021)

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ओफ्लोक्सासिन और उसकी मध्यवर्ती' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरूआत ।

फा. सं. 6/12/2021-डीजीटीआर.—यतः मै. आरती ड्रग्स लि. (जिसे यहां आगे 'आवेदक' या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ओफ्लोक्सासिन और उसकी मध्यवर्ती' (जिन्हें आगे "संबद्ध वस्तु" या विशेष रूप से "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का आरोप लगाया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह आवेदन मै. आरती ड्रग्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने न तो जांच की अवधि (पीओआई) में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक का समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद ओफ़्लॉक्सासिन और उसके मध्यवर्ती हैं, अर्थात् ओ-एसिड या ओफ़्लॉक्सासिन एसिड और ओ-ईस्टर या ओफ़्लॉक्सासिन ईस्टर। ओ-ईस्टर ओ-एसिड के उत्पादन के लिए अंतिम चरण है। ओ-ईस्टर के चरण से ओ-एसिड तक की प्रक्रिया एक वृद्धिशील प्रक्रिया है। ओ-ईस्टर को अम्लीय पानी में हाइड्रोलाइज किया जाता है, जिसे बाद में ठंडा किया जाता है और ओ-एसिड के फ्राइड केक बनाने के लिए फ़िल्टर किया जाता है, जिसे बाद में ओफ़्लॉक्सासिन प्राप्त करने के लिए प्रसंस्कृत किया जाता है। परिवर्तन के पिछले प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, आवेदक ने ओ-एसिड ओ-ईस्टर को भी उत्पाद के दायरे में जोड़ा है।
6. ओफ़्लॉक्सासिन का उपयोग ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और त्वचा, मूत्राशय, यूरिनरी ट्रेक्ट, प्रजनन अंगों और प्रोस्टेट के संक्रमण सहित कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। ओफ़्लॉक्सासिन, फ़्लोरोक्विनोलोन नामक एंटीबायोटिक दवाओं के एक वर्ग में है और संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। ओफ़्लॉक्सासिन-एसिड का ओफ़्लॉक्सासिन के उत्पादन में समर्पित उपयोग है।
7. ओ-एसिड ओफ़्लॉक्सासिन के उत्पादन के लिए समर्पित है और इसका कोई अन्य उपयोग नहीं है। ओ-एसिड और ओफ़्लॉक्सासिन दोनों के लिए बाज़ार एक समान रहता है। वर्तमान में, चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है।
8. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 और 30 के अंतर्गत आता है। ओफ़्लॉक्सासिन एचएस कोड 30042034 के अंतर्गत आता है हालाँकि, पीयूसी को विभिन्न अन्य एचएस कोडों अर्थात् 29419030, 29419060, 29152990, 29163990, 29189900, 29411090, 29349900, 29419090, 29420090 के तहत भी आयात किया गया है।

समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और भारत को संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु एक समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक (12 महीने) की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020 की अवधियां और जांच अवधियां शामिल होंगी।

सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। आवेदक ने यह बताया है कि यदि प्रतिवादी चीन के उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है, तो सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के उपबंधों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए। तदनुसार, नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।
13. आवेदक ने बताया है कि वह किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमतों अथवा भारत सहित ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों को कीमत संबंधी सूचना जुटाने में असमर्थ रहा है। अतः आवेदक ने चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य भारतीय घरेलू उत्पादन लागत में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ को जोड़कर युक्तियुक्त आधार पर निर्धारित किया है।
14. जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु आवेदक द्वारा सुझाई गई पद्धति पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

15. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, संभलाई प्रभार, समुद्री बीमा और बैंक प्रभार के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

16. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का निर्यात पाटित कीमतों पर किया गया है।

क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

17. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और बाजार में कीमतों में गिरावट आ रही है। उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सेदारी, लाभ, नियोजित पूंजी पर आय, नकद लाभ आदि के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में जांच की अवधि में गिरावट आई है। चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति होने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरूआत करते हैं।

प्रक्रिया

19. नियमावली के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमानजाँच में पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

20. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in और dd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
21. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध उनकी सरकार, भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

समय-सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in और dd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाये कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाली सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पत्र भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
30. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
32. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
33. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
34. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर/अनुरोध साझा करना

35. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि सभी हितबद्ध पक्षकार अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

(Case No. AD-OI-12/2021)

Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Ofloxacin and its intermediates” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/12/2021-DGTR.—Whereas M/s Aarti Drugs Limited (hereinafter referred to as the ‘Applicant’ or the ‘domestic industry’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules”) for Anti-dumping investigation concerning imports of “Ofloxacin and its intermediates” (hereinafter

referred to as the “subject goods” or specifically as “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. The Applicant has alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and have requested for initiation of anti-dumping investigation and imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Domestic Industry and Standing

3. The application has been filed by M/s Aarti Drugs Limited. The Applicant has neither imported the subject goods during the period of investigation from the subject country nor is related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or any importer of the product under consideration in India.
4. As per the evidence available on record, the production of the Applicant accounts for a major proportion of the total Indian production of the like article. In view of the above, the Authority notes that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Product under Consideration

5. The product under consideration in the present petition is Ofloxacin and its intermediates, namely, O-Acid or Ofloxacin Acid and O-Ester or Ofloxacin Ester. O-Ester is the penultimate stage for the production of O-Acid. The process from the stage of O-Ester to O-Acid is an incremental process. O-Ester is hydrolysed in acidic water, which is then cooled and filtered to form fried cakes of O-Acid, which are then further processed to obtain Ofloxacin. Considering, the past practice of circumvention, the applicant has combined O-Acid O-Ester also in the product scope.
6. Ofloxacin is used to treat certain infections including bronchitis, pneumonia, and infection of the skin, bladder, urinary tract, reproductive organs, and prostate. Ofloxacin is in a class of antibiotics called fluoroquinolones and works by killing bacteria that cause infections. Ofloxacin-Acid has dedicated use in the production of Ofloxacin.
7. O-Acid is dedicated to the production of Ofloxacin and has no other usage. The market remains the same for both O-Acid and Ofloxacin. Currently, no anti-dumping duties are in force on the subject goods originating in or exported from China PR.
8. Product under consideration falls under Chapter 29 and 30 of the Customs Tariff Act, 1975. Ofloxacin comes under HS code 30042034 However, the PUC has been imported also under various other HS Codes namely 29419030, 29419060, 29152990, 29163990, 29189900, 29411090, 29349900, 29419090, 29420090.

Like article

9. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods exported from the subject country to India. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

Subject Country

10. The subject country in the present investigation is China PR.

Period of Investigation

11. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2020 – March 2021 (12 Months). The injury period of investigation will, however, cover the periods 2017 – 18, 2018 – 19, 2019 – 20 and the POI.

Normal Value

12. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The Applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the Applicant that in case the responding Chinese Producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules. The normal value has accordingly been determined in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules.

13. The applicant has stated that it has not been able to gather information either with regard to costs or prices in a market economy third country, or price from such third country to other countries, including India. The applicant has thus determined normal value in China PR on other reasonable basis by taking Indian domestic cost of production and after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

14. For the purpose of initiation, the Authority has considered the methodology suggested by the applicant for determination of normal value.

Export Price

15. The export price for the subject goods from the subject country has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland freight, handling charges, marine insurance and bank charges.

Dumping Margin

16. Considering the normal value and export price determined, dumping margin determined is above de-minimis level. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject country is higher than the net export price, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country have been exported at dumped prices.

Evidence of Injury and Causal Link

17. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has claimed that the dumping of the product under consideration is causing material injury to the domestic industry. The imports are undercutting the prices of the domestic industry and causing price depression in the market. The performance of the domestic industry in respect of production, domestic sales, capacity utilization, market share, profits, return on capital employed, cash profits etc., have deteriorated. The overall performance of the domestic industry deteriorated in the POI. There is prima facie evidence of injury to the domestic industry by dumped imports from China PR.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

18. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Procedure

19. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of information

20. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg12-dgtr@gov.in; dir12-dgtr@gov.in and dd14-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word Format and data files are in MS Excel format.

21. The known producers/exporters in the subject country and their government through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the Product under consideration and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
24. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

Time-Limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in; dir12-dgtr@gov.in and dd14-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
29. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted

or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Sharing of responses/submission amongst interested parties

35. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to the ongoing global pandemic.

Non-cooperation

36. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority